भाजपा

लोक कल्याण
संकल्प पत्र-2017

परिवर्तन लाएंगे कमल खिलाएंगे

भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश

लोक कल्याण
संकल्प पत्र-2017

अनुक्रम

विषय	पृष्ठ संख्या
कृषि विकास का बने आधार	1
ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार	5
हर युवा को मिलेगा रोजगार	7
शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार	9
गरीबी से मुक्ति का सपना साकार	11
बुनियादी विकास मजबूत आधार	13
विकसित उद्योग सुगम व्यापार	15
सशक्त नारी समान अधिकार	17
स्वस्थ हो हर घर–परिवार	19
महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारा संकल्प	20

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश

विधान सभा चुनाव 2017

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन, विकास एवं गरीबों के सशक्तिकरण के लिए एक नए युग की शुरुआत इस ''लोक कल्याण संकल्प पत्र'' के माध्यम से कर रही है।

केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को जमीन पर उतारने की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण एवं उनके आर्थिक समायोजन के लिए अनेक साहसिक पहल की है। इस ''लोक कल्याण संकल्प पत्र'' के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यह आश्वस्त करती है कि उत्तर प्रदेश के सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशक विकास, गरीबों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण तथा युवाओं के आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करेगी।

भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि विगत पंद्रह साल में विकास पथ पर पिछड़ा उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष प्रगतिशील राज्य बने। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहले दिन से ही हमारा लक्ष्य राज्य को विकास एवं खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जाना होगा। प्रदेश के जनसाधारण की अपेक्षाओं के अनुरूप शासन में जन विश्वास की पुर्नस्थापना हमारा प्रमुख लक्ष्य रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के माध्यम से शासन–नीति तथा उसके क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम करेगी। इसके लिए भ्रष्टाचारियों एवं अपराधियों के प्रति सख्त रुख अपनाकर, उनको दण्डित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाती है कि उसकी लोक कल्याण के प्रति समर्पित सरकार प्रदेश को ऐसी व्यवस्था देगी जो स्थायी, संवेदनशील, जवाबदेह, ऊर्जावान एवं प्रगतिशील होने के साथ–साथ उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन–प्रवाह, ऐतिहासिक एवं पारंपरिक विरासत का पूर्ण सम्मान कर सके। हम ऐसे प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जहाँ पर प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं, जैसे– भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था, बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसर, जानमाल की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन की व्यवस्था हो। हम समाज के गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं समाज में उचित भागीदारी हेतु विशेष प्रयास करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम ऐसे प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि हो और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान हो। हमने ''लोक कल्याण संकल्प पत्र'' को इस विश्वास के साथ बनाया है कि आगामी पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष राज्य बने। इसके लिए हम कुछ विशिष्ट प्रयासों से अपनी पहल करेंगे। इस पहल के लिए हम अपने 9 संकल्प और उनकी प्राथमिकताएं इस ''लोक कल्याण संकल्प पत्र'' के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुँचा रहे हैं।

कृषि विकास का बने आधार

उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना, गोमती एवं गण्डक जैसी नदियों वाला उपजाऊ प्रदेश है। देश की कृषि परंपरा की सबसे पुरानी धरोहर उत्तर प्रदेश में है। सबसे समृद्ध जलस्रोत भी उत्तर प्रदेश में ही है। परन्तु, विगत पंद्रह सालों में सपा और बसपा के शासन में किसानों की हालत बद से बदतर हो गयी है। प्रदेश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए डेरी, पशु पालन, बागवानी, मत्सय पालन, जैविक खेती तथा फूड प्रोसेसिंग की विकास करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार कृषि, किसान और खेतिहर मजदूर तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास करेगी। कृषि ही प्रदेश के विकास का आधार बने, इस संरचना को हमारी पार्टी पूर्ण क्षमता के साथ लागू करेगी।

किसानों को आर्थिक मदद

- सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जाएगा
- सभी लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा
- भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की जाएगी
- सरकार बनने के 120 दिनों के भीतर बैंकों और चीनी मिलों के समन्वय से गन्ना किसानों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कराया जाएगा
- 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा

भूमिहीन कृषि मजदूरों का कल्याण

- भूमिहीन कृषि मजदूरों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएंगे
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ₹2 लाख तक का बीमा सरकार द्वारा निःशुल्क करवाया जाएगा
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को गौधन योजना के अन्तर्गत गाय और अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराये जाएंगे

धान खरीद एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य

- सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी की व्यवस्था करेगी
- किसानों को फसल का सही मूल्य दिलवाने के लिए सभी अनाज एवं सब्जी मंडियों को ई–मंडियों में बदला जाएगा
- आलू, प्याज और लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाएगा

कृषि का बुनियादी ढांचा

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुँचाया जाएगा
- सभी खेतों में कम दरों पर पर्याप्त बिजली पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी
- सभी किसानों को सरकार की ओर से एक नया 'एनर्जी एफीशिएंट पम्प' दिया जाएगा
- प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की पूरी व्यवस्था की जाएगी
- 3 साल में सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा
- नीलगाय एवं अन्य आवारा पशुओं से फसल की क्षति रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाएंगे

सिंचाई व्यवस्था

- प्रदेश के हर खेत में पानी पहुँचाने के लिए ₹20 हजार करोड़ के कोष के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फण्ड की स्थापना की जाएगी
- बुंदेलखंड के सूखा–ग्रस्त इलाकों तक सिंचाई योजनाओं को पहुँचाने के लिए इस फण्ड में राशि का अलग से प्रावधान किया जाएगा
- केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर काम प्राथमिकता से शुरू किया जाएगा
- प्रदेश की सभी ठप पड़ी ए.आई.बी.पी योजनाओं (जैसे बाणसागर नहर, कचनोडा बांध, मध्य गंगा नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना आदि) को तीव्र गति से पूरा किया जाएगा

कृषि विकास का बने आधार

- 50 लाख किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा
- तालाबों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए तालाब विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी
- प्रदेश की मौजूदा सिंचाई योजनाओं की खाली पड़ी क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा

बाढ़ बचाव

- बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए नदियों और बांधों की डी–सिल्टिंग एवं नए बांधों के निर्माण की व्यवस्था की जाएगी

दुग्ध विकास

- अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जाएगी और इसके लिए ₹15 करोड़ के डेरी विकास फण्ड की स्थापना की जाएगी
- दुग्ध संग्रह के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से हर 4 जिलों के समूह में 1 संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेरी की स्थापना की जाएगी

पशुपालन

- विगत शासन काल में उत्तर प्रदेश में पशु–धन की संख्या में गिरावट हुई है। दुधारु पशुओं की अवैध तस्करी से प्रदेश में डेरी जैसे उद्योग का विकास नहीं हो रहा है।
- सभी अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बंद किया जाएगा और सभी यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा
- गरीब परिवारों के पशुओं का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए पशु स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की जाएगी
- फसलों की क्षति रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर पशु संरक्षण की योजना बनाई जाएगी

बागवानी

- फल पट्टियों का विकास करके बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा

मत्स्य पालन

- मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और उससे जुड़े लोगों के कल्याण के लिए ₹100 करोड़ के कोष के साथ एक मत्स्य पालक कल्याण फंड की स्थापना की जाएगी

जैविक खेती

- प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रमाणीकरण संस्था गठित की जाएगी
- वर्मी कम्पोस्ट तथा गोबर गैस संयंत्रों के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा

फूड प्रोसेसिंग

- उत्तर प्रदेश को 'फूड पार्क राज्य' के रूप में विकसित किया जाएगा
- प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किये जाएंगे जहाँ पर पैकेजिंग, निर्यात और रिसर्च की सुविधा उपलब्ध होगी
- फूड प्रोसेसिंग पर आधारित लघु–उद्योग लगाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा

गन्ने की प्रोसेसिंग

- गन्ने से सीधे इथेनॉल बनाने का प्रयोगात्मक प्रयत्न किया जाएगा, जिससे गन्ना किसानों को गन्ने का सही मूल्य मिल पाएगा
- गन्ने से ग्लूटेन फ्री आटा, डिस्पोसेबल कटलरी आदि के उत्पादन को विशेष बढ़ावा दिया जाएगा

ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार

सपा के शासनकाल में प्रदेश में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी, महिलाओं पर अत्याचार, जमीनों के अवैध कब्जे एवं प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये ने प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रदेश की कानून और व्यवस्था की बदहाली ने विकास के अवसर एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीने के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में सरकार के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन्होंने पुलिस पर भी हमला करना शुरू कर दिया है और प्रशासन पंगु बनकर उनके आतंक के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। प्रदेश में जिनको भ्रष्टाचार के कारण मंत्री पद से हटाया गया, उन्हें तुरंत सरकार में वापस शामिल करके भ्रष्टाचारियों को सत्ता के संरक्षण का संदेश दिया गया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से गुंडाराज और भ्रष्टाचार के कलंक को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेती है।

पुलिस तंत्र में सुधार

- पुलिस में 1.5 लाख रिक्त पदों को, संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था का सम्मान करते हुए बिना जाति और धर्म के पक्षपात के, सिर्फ मेरिट के आधार पर भरा जाएगा
- पुलिस में सभी रिक्त आरक्षित पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा
- सांप्रदायिक तनाव के कारण पलायन रोकने के लिए पुलिस में एक विशेष विभाग बनाया जाएगा और हर जिले, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया जाएगा
- बेहतर निगरानी के लिए सभी पुलिस रिकॉर्ड डिजिटाइज किये जाएंगे
- पुलिस बल के भीतर एक विशेष कानून और व्यवस्था विंग स्थापित किया जाएगा। बेहतर जांच–पड़ताल और अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे
- सभी नागरिकों के लिए बिना जाति और धर्म के भेद–भाव के, भयमुक्त वातावरण में FIR दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाएगा
- अपराधों की जांच में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल कर गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए प्रदेश में 6 फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटोरियों की स्थापना की जाएगी
- जेलों का आधुनिकीकरण करके वैज्ञानिक पद्धति से जेल में बंद गैंगस्टरों को जेल से संगठित अपराध का संचालन करने से रोका जाएगा
- पैरोल पर फरार सभी भगोड़े अपराधियों को 45 दिनों के भीतर वापस जेल में डाला जाएगा

15 मिनट में पुलिस सहायता

- 100 हेल्पलाइन नंबर योजना में व्यापक स्तर पर सुधार एवं विस्तार करते हुए प्रदेश में कहीं भी कॉल करने के 15 मिनट के भीतर पुलिस सहायता सुनिश्चित कराई जाएगी

भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम

- हर जिले में 'एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स' स्थापित करके भू-माफियाओं द्वारा जब्त की गयी सारी जमीनों को मुक्त कराया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी
- पिछले 15 साल में सामने आये भ्रष्टाचार के सभी मामलों की त्वरित और निष्पक्ष जांच के लिए एक 'स्पेशल टास्क फोर्स' का गठन किया जाएगा
- अवैध खनन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सुदृढ़ खनन नीति की रचना की जाएगी और एक 'स्पेशल टास्क फोर्स' का गठन करके अब तक के अवैध खनन में लिप्त दोषियों को दण्डित किया जाएगा

भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार

- ग्रेड 3 और 4 की सरकारी नौकरियों में, संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था का सम्मान करते हुए बिना जाति और धर्म के पक्षपात के भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, इंटरव्यू को समाप्त किया जाएगा
- सरकार में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में विशेष हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी
- सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की जाएगी
- लोगों को सरकार की सभी सेवाओं को समय से उपलब्ध कराने के लिए सिटिजन चार्टर को सशक्त तरीके के लागू किया जाएगा
- प्रदेश में लोकायुक्त कानून को और मजबूत एवं प्रभावी बनाया जाएगा

न्याय सुधार

- प्रदेश के सभी नागरिकों को समयबद्ध, त्वरित एवं सुलभ न्याय का अधिकार दिया जाएगा
- प्रदेश के सभी मौजूदा कानूनों की समीक्षा करके असामयिक एवं अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया जाएगा
- उत्तर प्रदेश के न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित किया जाएगा

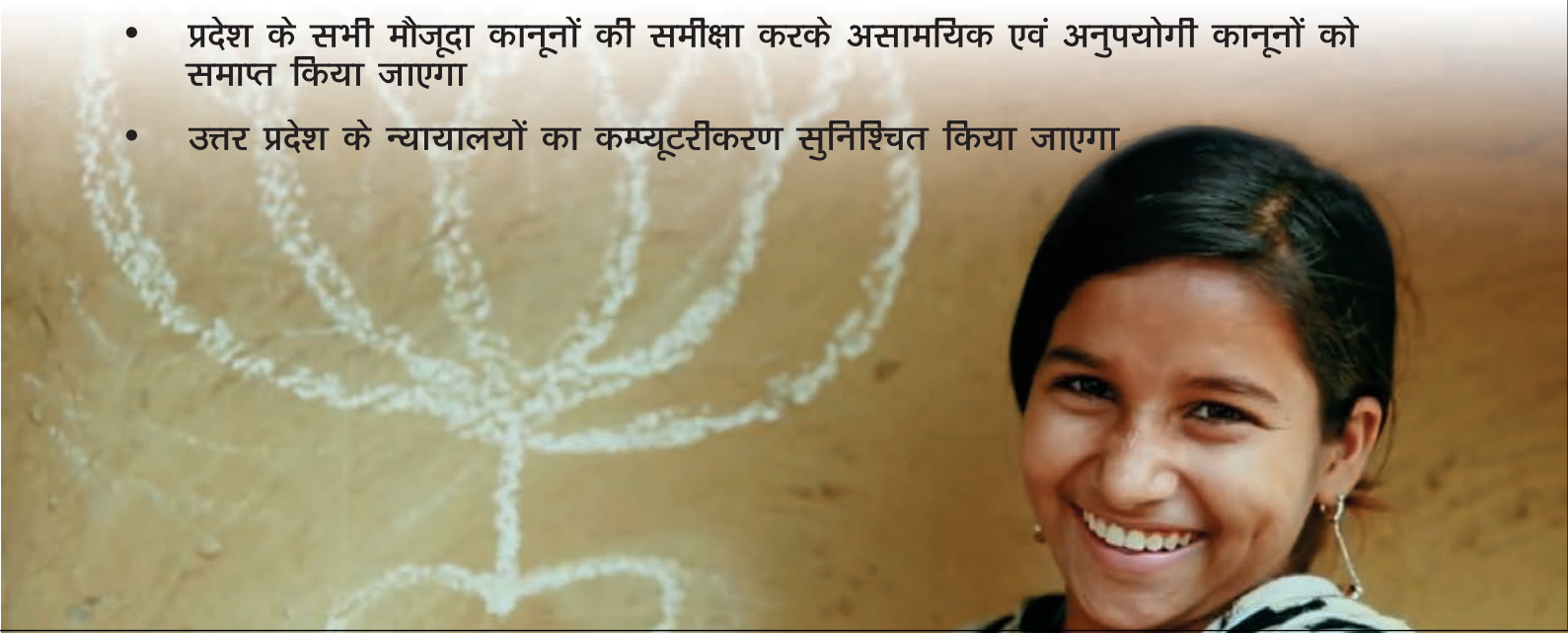

हर युवा को मिलेगा रोजगार

सपा और बसपा के पंद्रह वर्ष के शासनकाल में प्रदेश बदहाली के इस कगार पर पहुँच गया है कि नौजवान प्रदेश से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव और शहरी क्षेत्रों में भय के वातावरण ने प्रदेश में निवेश के अवसरों पर विराम चिन्ह लगा दिया है। प्रदेश के युवाओं की शिक्षा एवं कौशल विकास में सपा सरकार पूर्णतया असफल सिद्ध हुई है। सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पक्षपात पर स्वयं उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर चेयरमैन को पद से हटाया। प्रदेश सरकार की हर भर्ती प्रक्रिया एक घोटाला बनकर सामने आई। भारतीय जनता पार्टी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को सख्ती से लागू करेगी। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के ऐसे अवसरों का निर्माण करेगी, जिससे वे अपने गाँव, कस्बे और शहर में जीवन के विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे।

हर हाथ को काम का अधिकार

- अगले 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्व–रोजगार के अवसर पैदा किये जाएंगे
- उत्तर प्रदेश में स्थापित हर उद्योग में 90% नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा
- सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी रिक्त सरकारी पदों के लिए पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी
- हर घर के एक सदस्य को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा

स्टार्ट–अप योजनाएं

- ₹1 हजार करोड़ के स्टार्ट–अप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी से स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा
- देश का सबसे बड़ा स्टार्ट–अप इनक्यूबेटर राज्य में स्थापित किया जाएगा

कौशल विकास केंद्र

- प्रत्येक तहसील में आधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी जो आई.टी., बी.पी.ओ., लोजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन आदि जैसे स्किल पर केंद्रित होंगे
- इन केन्द्रों में युवाओं को प्लेसमेंट सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी

मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट

- प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेद–भाव के मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा
- राज्य के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के अन्तर्गत प्रति माह 1 जीबी इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा

शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार

उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं सांस्कृतिक विषयों में हमेशा देश का अग्रणी राज्य रहा है। परंपरा से ही काशी शिक्षा का सनातन केंद्र रहा है। आधुनिक भारत में भी महामना मदन मोहन मालवीय जी ने उस परंपरा को प्रगतिशीलता के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई। परन्तु सपा व बसपा के शासनकाल में यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार बना, जिसके कारण शैक्षिक गुणवत्ता का पतन हुआ एवं मूलभूत शिक्षा के अवसरों में गिरावट आई। भारतीय जनता पार्टी बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश में समान अवसरों की उपलब्धता की दिशा में कार्य करेगी।

निःशुल्क शिक्षा

- सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी
- सभी लड़कों के लिए कक्षा 12 तक तथा कक्षा 12 में 50% से अधिक पाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी
- गरीब परिवारों से आए छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए ₹500 करोड़ के बाबा साहेब अम्बेडकर छात्रवृति कोष की स्थापना की जाएगी
- कक्षा 12 तक गरीब परिवारों से आए छात्र–छात्राओं को सभी पुस्तकें, स्कूल यूनिफार्म, जूते तथा स्कूल बैग मुफ्त दिए जाएंगे

शिक्षा संस्थानों का विस्तार

- उत्तर प्रदेश में 10 नए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी
- हर जिले में एक इंजीनियरिंग अथवा पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी
- सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
- सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का आधुनिकीकरण किया जाएगा
- प्राइवेट स्कूलों की फीस व्यवस्थित करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा
- प्रदेश के कॉलेज व विश्वविद्यालय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए विशेष जोर दिया जाएगा

- विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की अक्रेडीटेशन (मान्यता) की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था आरम्भ की जाएगी
- प्रत्येक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक एवं एक कक्ष के न्यूनतम अनुपात को शत–प्रतिशत लागू किया जाएगा।

शिक्षा मित्रों की न्यायोचित सहायता

- प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार समस्या को 3 महीनों में न्यायोचित तरीकों से सुलझाया जाएगा

संस्कृत शिक्षा

- उत्तर प्रदेश में एक नए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
- प्राथमिक शिक्षा से योग शिक्षकों को शारीरिक शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाएगा
- संस्कृत शिक्षकों की वेतन–विसंगति को दूर किया जाएगा
- पर्यटन स्थलों पर संस्कृतिज्ञों की पर्यटन गाइड के रूप में नियुक्ति की जाएगी
- संस्कृत अकादमी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन के साथ एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी

गरीबी से मुक्ति का सपना साकार

भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में शासन में आने के बाद गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनधन योजना से लेकर नोटबंदी तक के सभी निर्णयों ने देश के गरीब कल्याण के रास्ते में आने वाले अवरोधों को दूर किया है। उनके इन प्रयासों से कालेधन पर चोट लगी है और गरीबों के जीवन में परिवर्तन के रास्ते खुले हैं। देश में गरीबी का मूल कारण भ्रष्टाचार एवं कुशासन है। पार्टी अपनी सुशासन की विचारधारा के मार्ग पर चलते हुए अन्त्योदय के लक्ष्यों को हासिल करेगी।

गरीब कल्याण कार्ड

- प्रदेश के सभी गरीबों तक बिना जाति और धर्म के भेद–भाव के सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 'गरीब कल्याण कार्ड' का वितरण किया जाएगा
- यह गरीब कल्याण कार्ड बी.पी.एल एवं राशन कार्ड धारकों को सरकारी सुविधाओं का पारदर्शी तरीके से हस्तांतरण करेगा
- जनधन एवं आधार योजना की नींव पर बनी यह गरीब कल्याण कार्ड योजना प्रदेश के आर्थिक समावेश एवं सामाजिक उत्थान के लिए एक क्रांतिकारी पहल होगी

गरीब कल्याण योजनाएं

- प्रत्येक गरीब को गरीब कल्याण कार्ड के जरिये सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सर्जरी, क्रिटिकल केयर सहित सभी प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं कैशलेस तरीके से प्राप्त होंगी
- गरीब कल्याण कार्ड के जरिये 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए ₹6 लाख तक का आवास ऋण रियायती दरों पर दिया जाएगा
- गरीब कल्याण कार्ड धारकों को राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी, गुड़ आदि न्यूनतम दाम पर उपलब्ध कराया जाएगा

- हर जिले में आश्रयहीनों के लिए पर्याप्त रैन बसेरों का निर्माण किया जाएगा
- शहरी झुग्गी–झोपड़ियों के स्थानांतरण एवं पुनर्वास के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई जाएगी

सामान्य निर्धन वर्ग आयोग

- सामान्य वर्ग के गरीबों की आर्थिक प्रगति के लिए सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा

असंगठित श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं

- सभी असंगठित श्रमिकों (ठेला गाड़ी चालक, दुकानों–होटलों में काम करने वाले, घरों में काम करने वाले महिला–पुरुषों, फुटकर हलवाई के साथ कर्मचारी, साइकिल रिक्शा चालकों, अखबार बांटने वाले श्रमिक, इत्यादि) के लिए दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत ₹2 लाख तक का सुरक्षा बीमा सरकार द्वारा निःशुल्क करवाया जाएगा
- अटल पेंशन योजना का लाभ सभी असंगठित श्रमिकों तक पहुँचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा
- महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर समिति गठित की जाएगी

बुनियादी विकास मजबूत आधार

गाँव, क़स्बा शहरी विकास

पिछली सरकारों द्वारा राज्य में विकास के बड़े–बड़े दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जो देश के अन्य भागों के लोगों को आसानी से सुलभ हैं। स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश के गाँव और कस्बे बिजली, सड़क एवं पीने योग्य पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

राज्य में बुनियादी ढांचे में मौलिक परिवर्तन कर गाँवों, कस्बों और शहरों में रहने वाले उत्तर प्रदेशवासियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। भ्रष्टाचार के बगैर सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर बुनियादी ढांचे का विकास करते हुए राज्य के गाँवों, कस्बों और शहरों को तेज प्रगति के पथ पर लाया जाए, पार्टी इसके लिए भी प्रतिबद्ध है।

बुनियादी सुविधाएं

- प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी
- सभी गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किए जाएंगे
- सभी गरीब घरों को बिजली की पहली 100 यूनिट ₹3 प्रति यूनिट की रियायती दर पर दी जाएगी
- पाइप कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए भागीरथी योजना शुरू की जाएगी
- अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी घरों में शौचालय बनाने का काम पूरा किया जाएगा
- सभी गरीब घरों को नि:शुल्क एल.पी.जी कनेक्शन दिया जाएगा
- प्रदेश के सभी महानगरों में पाइप के माध्यम से पी.एन.जी रसोई गैस पहुँचाई जाएगी

ग्रामीण विकास योजनाएं

- प्रदेश के सभी गांवों को मिनी–बस सेवा के द्वारा शहर से जोड़ा जाएगा
- सभी पंचायत कार्यालय भवनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा
- सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 4 ग्राम पंचायतों के लिए एक चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना की जाएगी
- राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक व्यवस्था को सुदृढ़ करके ग्रामीण विकास का अहम् हिस्सा बनाया जाएगा
- भारत सरकार तथा नैशनलाइज्ड एवं कमर्शियल बैंकों के सहयोग से 25 हजार गाँवों में बैंक शाखाएं उपलब्ध कराई जाएंगी

शहरी विकास योजनाएं

- लखनऊ, नोएडा में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा तथा कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा आरंभ की जाएगी
- सभी प्रमुख शहरों में वातानुकूलित बस सेवा शुरू करके सार्वजनिक यातायात को और आरामदायक बनाया जाएगा
- शहरों में रिंग रोड, बाईपास, अंडरपास और फ्लाई–ओवर का निर्माण किया जाएगा
- मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैंड इत्यादि) पर मुफ्त 'वाई–फाई (Wi-Fi)' की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

बुनियादी ढांचा

- मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश को आपस मे बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा
- प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों की बाकी देश से हवाई कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए एयरपोर्टों का निर्माण किया जाएगा
- प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों के मुख्य पर्यटन स्थलों (लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिशारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि) को हेलीकाप्टर सेवा के जरिये आपस में जोड़ा जाएगा

बुंदेलखंड विकास बोर्ड

- बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा

पूर्वांचल विकास बोर्ड

- पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा

विकसित उद्योग सुगम व्यापार

उत्तर प्रदेश की व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। प्रदेश के कुशल कारीगरों एवं व्यापारियों के समन्वय ने प्रदेश की अनेक हस्तशिल्प कलाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई है। प्रदेश की अपनी विशिष्ट परंपराओं एवं क्षमताओं के कारण अनेक लघु उद्योगों के माध्यम से निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीक, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि वह प्रदेश के उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के समाधान एवं उनके कार्य–विस्तार के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेगी।

उद्योग विकास

- प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी
- सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग बनाया जाएगा
- प्रदेश में निवेश की राशि को तीन गुना बढ़ाने के लिए एक विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना की जाएगी
- प्रदेश में टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6 आई.टी. पार्कों की स्थापना की जाएगी
- प्रदेश में अंग्रेजी दवाओं की आवश्यकता एवं खपत को पूरा करने के लिए फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशाल औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

- ₹1000 करोड़ की कोष निधि के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत बढ़ई, मोची, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि जैसे पारंपरिक स्व–रोजगारियों को ऋण, उपकरण, तकनीकी सहायता और बाजार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी
- प्रदेश के हर जिले के स्थानीय व्यापारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा – बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, मेरठ में खेल का सामान, फ़िरोज़ाबाद में कांच, अलीगढ में ताले, रामपुर में चाकू, मुरादाबाद में पीतल, सम्भल में मिंट, बरेली में फर्नीचर, कन्नौज में इत्र, आगरा

में जूता और पेठा, कानपूर में चमड़ा, भदोही में कालीन, बनारस में साड़ी, बलरामपुर में चीनी, मुज़फ़्फ़रनगर में गुड़, लखनऊ में चिकनकारी आदि

व्यापारी कल्याण

- प्रदेश में व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी
- व्यापारियों के विवादों को सुलझाने के लिए हर एक जिले में एक विशेष मध्यस्थता प्राधिकरण का गठन किया जाएगा
- प्रदेश में व्यापार करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को सरल एवं सुगम बनाया जाएगा, जिससे व्यापारियों को व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा

लघु और पारंपरिक पेशेवर

- समर्पित ट्रेनों और फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से बुनकरों तथा उत्तर प्रदेश के अन्य पारंपरिक हस्तशिल्पों की बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी
- सरकार समर्थित लॉजिस्टिक्स के साथ एक ई–कॉमर्स पोर्टल स्थापित किया जाएगा जिसके द्वारा प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्पों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाया जाएगा
- प्रदेश के 6 क्षेत्रों में से प्रत्येक में हस्तशिल्प केंद्र स्थापित करके पेशेवरों को विनिर्माण, अनुसंधान एवं बाजार की समझ की आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा
- लखनऊ में एक स्थायी प्रदर्शनी एवं निर्यात केंद्र को स्थापित कर, अन्य शहरों और कस्बों में स्थायी हाट स्थापित किये जाएंगे
- अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा समाज के लोगों को हस्तशिल्प और गृह उद्योग के व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाएगा

सशक्त नारी समान अधिकार

उत्तर प्रदेश में सपा एवं बसपा की सरकारों द्वारा महिलाओं की अनदेखी की गयी है। उन्हें प्रदेश की उन्नति में सहयोगी बनाने की जगह उनके साथ संस्थागत भेदभाव किया गया है। उनके खिलाफ अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के विकास की वाहक के रूप में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ये आश्वस्त करती है कि सरकार बनने के बाद महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी।

भाग्य लक्ष्मी योजना

- प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर ₹50 हजार का विकास बॉण्ड दिया जाएगा। बेटी के कक्षा 6 में पहुँचने पर ₹3 हजार, कक्षा 8 में पहुँचने पर ₹5 हजार, कक्षा 10 में पहुँचने पर ₹7 हजार और कक्षा 12 में पहुँचने पर ₹8 हजार दिए जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष की होने पर ₹2 लाख दिए जाएंगे।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- कन्याओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा
- गरीब परिवारों में बेटी के जन्म लेने पर ₹5001 धनराशि गरीब कल्याण कार्ड के माध्यम से बेटी की माँ को दी जाएगी

महिलाओं की सुरक्षा

- तीन नई महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना की जाएगी– अवंती बाई बटालियन, झलकारी बाई बटालियन और ऊदा देवी बटालियन
- महिला उत्पीड़न के मामलों के लिए 1000 महिला अफसरों का विशेष जांच विभाग और 100 फास्ट–ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जाएंगे
- सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित तीन तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में उनका पक्ष रखेगी
- प्रत्येक पुलिस थाने में पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सुनिश्चित की जाएगी

- प्रदेश के हर जिले में 3 महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किये जाएंगे
- हर कॉलेज के नजदीकी पुलिस थाने में छात्राओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए एंटी–रोमियो दल बनाये जाएंगे
- शहरी झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा
- गाँव की महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाये जाएंगे

आंगनबाड़ी कर्मी

- प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में वृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार अतिआवश्यक है
- सरकार में आने के बाद एक समिति का गठन करके 120 दिनों में उसकी रिपोर्ट के आधार पर उनके मानदेय में न्यायोचित वृद्धि की जाएगी

आशा बहू

- ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा बहुओं का कार्य एवं सेवा एक महत्वपूर्ण कड़ी है
- सरकार में आने के बाद एक समिति का गठन करके 120 दिनों में उसकी रिपोर्ट के आधार पर उनके मानदेय में न्यायोचित वृद्धि की जाएगी

विधवा पेंशन

- विधवा पेंशन की राशि को बढ़ाकर ₹1 हजार किया जाएगा
- विधवा पेंशन के लिए उम्र की सीमा को समाप्त किया जाएगा

स्वस्थ हो हर घर-परिवार

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत संरचना एवं बुनियादी सुविधाओं को जरुरतमंदों तक पहुंचाने में सपा–बसपा की सरकारें असफल रही हैं। सपा एवं बसपा के राज में स्वास्थ्य घोटालों की गूँज बनी रही, परन्तु उसका संज्ञान लेने में ये सरकारें विफल रहीं। नतीजतन गरीब परिवारों को प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र की आधारभूत संरचना में सुधार, दवाइयों की उपलब्धता एवं आवश्यक स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति को मिशन मोड पर पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है।

15 मिनट में एम्बुलेंस सेवा

- 108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार और सुधार करके कॉल करने के 15 मिनट के भीतर आधुनिक एम्बुलेंस दूर–दराज के इलाकों तक पहुँचाई जाएगी

स्वास्थ्य संस्थानों में सुधार

- हर गाँव में आधुनिक सुविधा से लैस प्राथमिक उप–स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे
- हर ब्लॉक में जेनेरिक दवा देने वाले दवाखाने शुरू किये जाएंगे
- प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेज एवं सुपर–स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किये जाएंगे
- प्रदेश के 6 क्षेत्रों में 1 AIIMS स्तर का संस्थान स्थापित किया जाएगा
- सभी अस्पतालों में प्रसव कक्ष को अत्याधुनिक बनाया जाएगा

कुपोषण से मुक्ति

- अगले 5 साल में प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए शबरी संकल्प अभियान चलाया जाएगा

भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ

- योग, आयुर्वेद, होम्योपथी, नेचुरोपैथी तथा अन्य प्रचलित भारतीय चिकित्सा पद्यतियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा

महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारा संकल्प

भारतीय जनता पार्टी यह आश्वस्त करती है कि प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास के साथ–साथ सामाजिक, शासकीय, पर्यावरण, सांस्कृतिक एवं विभिन्न वर्गों, जैसे– पूर्व सैनिक, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग इत्यादि के विषयों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना आवश्यक है। अतएव इन महत्वपूर्ण संकल्पों को भी लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त करती है।

सांस्कृतिक विरासत

- भाजपा का उन मुद्दों पर स्पष्ट रुख है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े हैं
- राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है – संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण

- प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज हुए मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए सरकार 25 नई विशेष अदालतों का गठन करेगी
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाएगी तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय की सीमा भी बढ़ाई जाएगी
- अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु रियायती ब्याज़ दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा
- अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के बी.पी.एल परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी
- अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों में बाबा साहेब अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र बनाये जाएंगे
- अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के उद्यमियों का स्वरोजगार हेतु ऋण तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी

महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारा संकल्प

पर्यटन

- मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिशारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास कर प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट बनाये जाएंगे, जैसे राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट आदि
- पर्यटकों की जानकारी, बुकिंग सहायता आदि के लिए एक समर्पित 24X7 राज्य पर्यटन हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी
- सभी तीर्थ स्थलों को 4 लेन राजमार्ग के साथ जोड़ा जाएगा

सांस्कृतिक विकास

- लोक कलाकारों के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा
- फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए अनुदान दिया जाएगा
- लोक कलाकारों के वाद्य यंत्रों हेतु अनुदान दिया जाएगा
- भारत भवन के तर्ज पर कला परिषद् की स्थापना की जाएगी
- आंचलिक भाषाओं एवं लोक विधाओं के विकास हेतु कबीर अकादमी की स्थापना की जाएगी
- महानगरों के साथ– साथ जिला केन्द्रों पर कला उत्सव आयोजित किये जाएंगे

नमामि गंगे

- केंद्र सरकार की सहायता से गंगा, यमुना और उनकी उपनदियों को साफ करने के लिए प्राथमिकता से कदम उठाए जाएंगे
- इन नदियों के किनारे बसे सभी गाँवों में सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी ताकि गन्दा पानी नदी में छोड़े जाने से पहले साफ हो सके

पर्यावरण

- प्रदेश के सभी बड़े–छोटे शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रभावी तथा पर्यावरण हितैषी व्यवस्था की जाएगी
- कचरे का ऊर्जा के रूप में पुनरू नवीनीकरण करने की व्यवस्था की जाएगी
- चमड़े के कारखानों और बुचड़खानों के पास के इलाको में गंदे पानी को साफ

करने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्रणाली लगाई जाएगी और आस–पास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा

- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल सस्ते दरों पर उपलब्ध कराये जाएंगे
- सामाजिक वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा
- राष्ट्रीय पर्वों पर सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें फलदार वृक्षों को बढ़ावा दिया जाएगा

पुलिसकर्मी कल्याण

- पुलिसकर्मियों व उनके परिवारों के लिए प्रदेश के बड़े शहरों में स्कूल सहित शहीद रोशन सिंह रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाई जाएगी
- पुलिसकर्मियों के सेवा हालात, प्रमोशन और वेतन ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा
- पुलिसकर्मियों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए गृहमंत्री की निगरानी में ग्रीवेंस सेल बनाई जाएगी
- पुलिस दल और उनके परिवारों के लिए मुफ्त चेक–अप के लिए स्वास्थ्य कैंप आयोजित किए जाएंगे

सरकारी कर्मचारी कल्याण

- सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए ₹2 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा
- सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 'कर्मयोगी अभियान' शुरू किया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों को उनकी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा

पूर्व सैनिक कल्याण

- सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर अनुदान से इकट्ठा की गयी राशि की तीन गुना राशि सरकार द्वारा दी जाएगी
- पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं द्वारा लिए गए ₹3 लाख तक के ऋण की ब्याज दरो में 4% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा

महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारा संकल्प

अधिवक्ता कल्याण

- अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि की आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया जाएगा
- अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि ₹1.5 लाख से बढ़ा कर ₹5 लाख की जाएगी
- युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 3 सालों के लिए किताब और पत्रिका खरीदने हेतु सालाना ₹5 हजार की वृत्ति दी जाएगी

वरिष्ठ नागरिक कल्याण

- प्रदेश में 'वरिष्ठ नागरिक मित्र' सेवा आरम्भ कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सरकारी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को उनके दरवाजे पर मिलें
- वृद्धावस्था पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1 हजार प्रतिमाह किया जाएगा
- वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का दायित्व सरकार निभायेगी

दिव्यांग कल्याण

- सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटे के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा
- दिव्यांगों को रोजगार हेतु सरल शर्तों पर ऋण दिया जाएगा
- सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी ए.टी.एम दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक हों

खेल

- सरकारी और निजी भागीदारी से ₹500 करोड़ की राशि वाले एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना होगी, जो पहले से मौजूद स्पोर्ट्स कॉलेजों को पुनर्जीवित करेगी और छात्रों को राज्य द्वारा स्पोर्ट्स फेलोशिप प्रदान की जाएगी
- सरकारी और निजी भागीदारी से आधुनिक सुविधाओं से लैस स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला जाएगा
- सभी स्तर के खिलाड़ियों को मासिक विकास राशि दी जाएगी
- प्रदेश की सभी टीमों के लिए सरकार ट्रेनिंग, पोषक आहार एवं अंतर्राष्ट्रीय कोच का इंतजाम करेगी
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैडल जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों के सम्मान हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी

2014 के लोक सभा चुनावों में ऐतिहासिक जनादेश हासिल करने के बाद 20 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है। यह सरकार सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशक विकास की सरकार है।

प्रधानमंत्री जी स्वयं उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त सहायता राशि मिलने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ–जहाँ शासन में रही है, हमने वहाँ–वहाँ विकास किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सभी को हमने बीमारू राज्य की कैटेगरी से मुक्त किया है। सपा व बसपा के कुशासन एवं भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश अभी भी बीमारू राज्य बना हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को बदलने के लिए कृतसंकल्प है। हम उत्तर प्रदेश की जनता से आवाहन करते हैं कि वह आगामी चुनाव में परिवर्तन के संकल्प में समर्थन एवं आशीर्वाद दें।

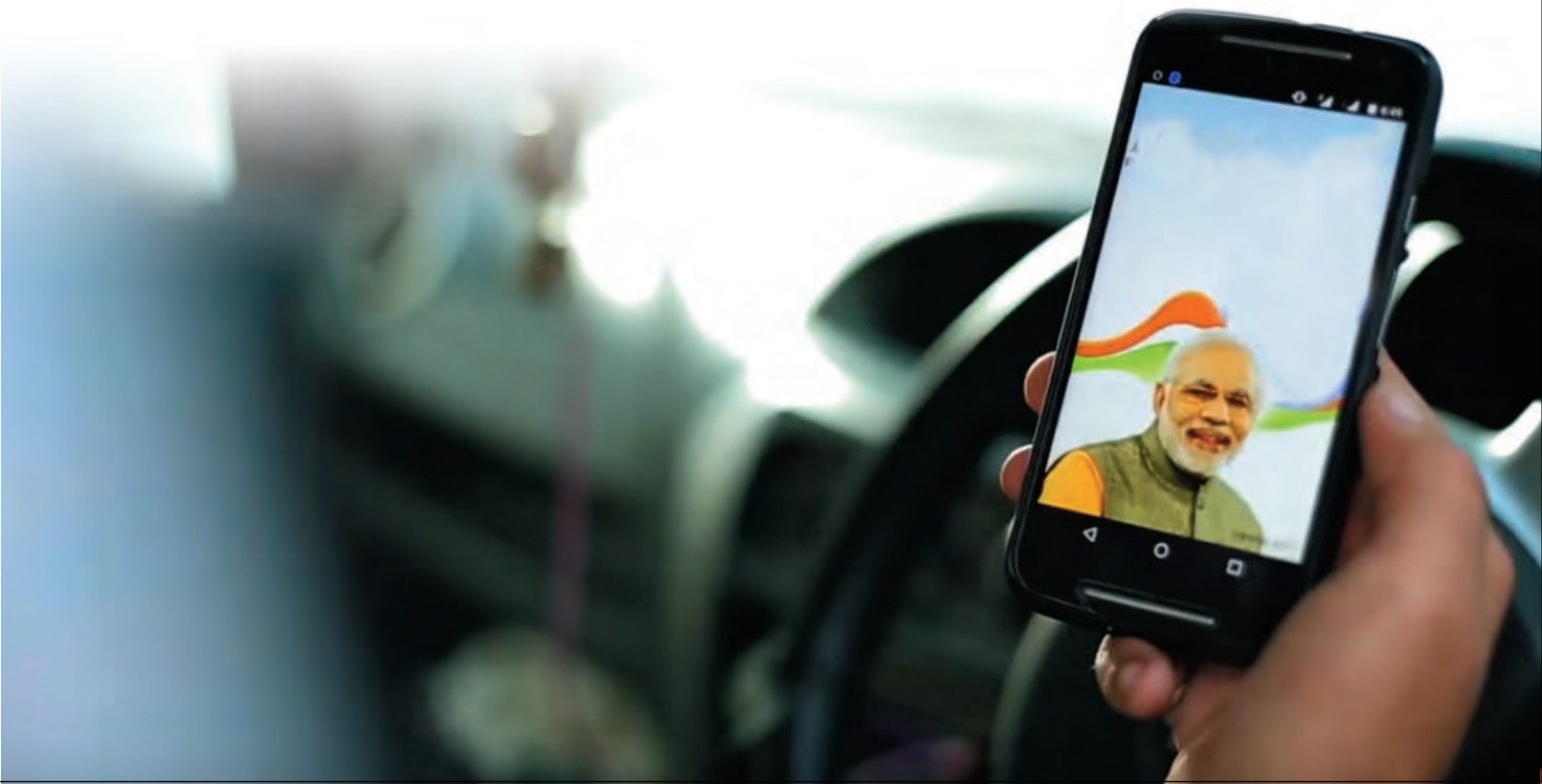

नोट्स

“राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा
सुशासन और विकास से
अन्त्योदय हमारा लक्ष्य”

—पं. दीनदयाल उपाध्याय

Published by: Bharatiya Janata Party, Lucknow, Uttar Pradesh
Printed by: Printco Printers, 22, Jagat Narain, Lucknow. Qty.: 5000

भाजपा

भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी